




## 9 Incidents: Kannada for All, Except Minorities: Karnataka's Controversial Language Policy

कर्नाटक में जहां कन्नड़ समर्थक संगठन हिंदी का विरोध करते हैं, वहीं श्रम मंत्री संतोष लाड का 22 मई 2025 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक मुस्लिम व्यक्ति से कन्नड़ नहीं, बल्कि हिंदी-उर्दू में बात करते दिखते हैं। यह दिखाता है कि विरोध हिंदी से है, न कि अन्य भाषाओं से।

यह रिपोर्ट वर्ष 1994 से 2025 तक कर्नाटक सरकार की नीतियों में कन्नड़ के स्थान पर उर्दू को प्राथमिकता देने और मुस्लिम संगठनों द्वारा कन्नड़ के बजाय उर्दू तथा हिंदी भाषा के प्रयोग से जुड़ी 9 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है।

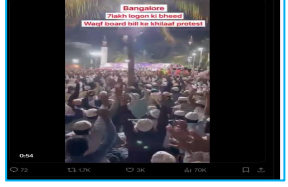


क्रमांक	स्थान	विवरण	चित्र /स्रोत
<b>कर्नाटक सरकार की नीतियों में कन्नड़ के जगह उर्दू को प्राथमिकता</b>			
1)	7 मार्च, 2025  कर्नाटक	<p><b>कर्नाटक सरकार का बजट मुस्लिमों और उर्दू के नाम</b></p> <p>कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च 2025 को पेश किए गए अपने 16वें बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए कई विशेष प्रावधान किए। बजट में मदरसों, कब्रिस्तानों, हज भवन, मौलवियों की तनख्वाह, जैसे कदम शामिल थे।</p> <p>मुस्लिमों को 4% सरकारी टेंडर आरक्षण देने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने उर्दू माध्यम के स्कूलों को सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से मदरसों में औपचारिक शिक्षा और सीनियर सेकेंड्री परीक्षा की तैयारी के लिए सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस बजट को भाजपा ने 'मुस्लिम लीग बजट' कहते हुए आलोचना की।</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">amarujala</a></p>
2)	20 मई, 2024  मडिकेरी (कर्नाटक)	<p><b>आंगनवाड़ी में उर्दू ज़रूरी, भाजपा ने बताया कन्नड़ भाषियों के साथ अन्याय</b></p> <p>कर्नाटक सरकार ने 20 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर मडिकेरी और चिकमंगलूरु जिलों में आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। इस पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मुस्लिम तुष्टिकरण करार दिया और कन्नड़ भाषियों के अधिकारों की अनदेखी बताया। सरकार के इस आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 25% से अधिक है, वहाँ उर्दू जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उपनिदेशक को लिखे पत्र में विभाग ने बताया कि स्थानीय जनसंख्या में विभिन्न समुदाय शामिल हैं और मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 31.94% है। सरकार की नीति के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक हो, वहाँ ऐसी भाषाओं में दक्ष कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।</p> <p>भाजपा के पूर्व सांसद नलिन कुमार कटील ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा, "आंगनवाड़ी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए उर्दू जानना अनिवार्य करना अस्वीकार्य है। यह कांग्रेस की मुस्लिम समुदाय को खुश करने की एक और कोशिश है और इससे अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित हो रहे हैं। यह एक खतरनाक राजनीतिक चाल है।"</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">indiatoday</a></p>

<p>3)</p> <p>16 जनवरी, 2022</p> <p><b>बेंगलुरु</b> (कर्नाटक)</p>	<p><b>मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दी उर्दू भाषा सीखने की सलाह</b></p> <p>कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पुलिस के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 31 दिसंबर 2013 को आयोजित एक समारोह में पुलिस अधिकारियों को उर्दू भाषा सीखने की सलाह दी।</p> <p>उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा का प्रयोग कर पुलिस जनता से अधिक विनम्रता और तहज़ीब से संवाद कर सकती है, जिससे लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धारमैया ने यह भी उल्लेख किया कि सभी लोगों से एक ही भाषा में बात नहीं की जा सकती, इसलिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है।</p>	 <p><a href="#">Xlink</a></p>
<p>4)</p> <p>29 जून, 2022</p> <p><b>उत्तर कन्नड़</b> (कर्नाटक)</p>	<p><b>नगर परिषद पर उर्दू साइनबोर्ड को लेकर बढ़ा तनाव</b></p> <p>उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल कस्बे में जब नगर परिषद भवन पर लगाए गए साइनबोर्ड में कन्नड़ और अंग्रेज़ी के साथ उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया गया। भटकल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है और स्थानीय लोग उर्दू साइनबोर्ड का समर्थन कर रहे हैं। यह दूसरी बार है जब परिषद ने उर्दू में साइनबोर्ड लगवाए हैं</p> <p>पिछली बार विरोध के चलते इन्हें हटा दिया गया था। भटकल एक संवेदनशील इलाका माना जाता है और अतीत में सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रहा है। वर्तमान तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है।</p>	 <p><a href="#">news18</a></p>
<p>5)</p> <p>31 अक्टूबर, 1994</p> <p><b>बेंगलुरु</b> (कर्नाटक)</p>	<p><b>उर्दू समाचार प्रसारण पर कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु में 1994 में दूरदर्शन केंद्र ने उर्दू भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से कुछ कन्नड़ समर्थक संगठनों और स्थानीय जनसमूह में असंतोष पैदा हुआ, जिन्होंने इसे कन्नड़ भाषा के हक पर खतरा माना और हिंदी-उर्दू के प्रभाव को लेकर विरोध शुरू किया।</p> <p>विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक रूप ले गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव और झड़पें हुईं। इन दंगों में कई लोगों की जान गई और शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। घटना ने कर्नाटक की सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं और भाषाई संघर्षों को उजागर किया।</p>	 <p><a href="#">indiatoday</a></p>

## मुस्लिम और कांग्रेसी संगठनों द्वारा कन्नड़ की जगह उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग

6)	22 मई, 2025  कर्नाटक	<p><b>उर्दू में बात कर रहे मंत्री लाड पर तुष्टिकरण के आरोप</b></p> <p>कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान अचानक कन्नड़ से उर्दू और हिंदी में बोलने लगे। यह तब हुआ जब सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम 'सलीम' बताया। इस पर मंत्री लाड ने तुरंत भाषा बदल ली और उर्दू-हिंदी में संवाद जारी रखा।</p> <p>इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे एक नेता की भाषाई संवेदनशीलता और बहुभाषी समाज में संवाद स्थापित करने की क्षमता के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ा। हालांकि, मंत्री लाड की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">X link</a></p>
7)	22 मई, 2025  कर्नाटक	<p><b>हिंदी विरोध की लहर के बीच सीएम सिद्धारमैया ने की उर्दू में बातचीत</b></p> <p>सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक मुस्लिम युवक से उर्दू में बातचीत करते नजर आ रहे हैं—वह भी उस वक्त जब राज्य में हिंदी विरोध की लहर तेज़ है।</p> <p>वीडियो में मुख्यमंत्री का यह सहज उर्दू प्रयोग कई सवाल खड़े करता है: क्या यह सांस्कृतिक समावेशिता है या राजनीतिक तुष्टिकरण? कुछ लोगों ने इसे समुदायों से संवाद स्थापित करने की कोशिश बताया, तो कई यूज़र्स ने इसे "नकली सेव्युलरिज़्म" कहकर आलोचना की।</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">X link</a></p>
8)	21 मई, 2025  कर्नाटक	<p><b>हिंदी विरोध के बावजूद प्रियांक खड़गे का हिंदी और उर्दू में संवाद</b></p> <p>सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के विधायक प्रियांक खड़गे कर्नाटक की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए हिंदी और उर्दू में बातचीत कर रहे हैं। जबकि पूरे कर्नाटक में हिंदी भाषा के विरोध की लहर चल रहा है, प्रियांक खड़गे के इस भाषाई प्रयोग पर कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला।</p> <p>यह घटना कर्नाटक की राजनीतिक और सांस्कृतिक जटिलताओं को उजागर करती है, जहां एक ओर हिंदी के विरोध की आवाजें उठ रही हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं द्वारा हिंदी और उर्दू का प्रयोग समुदायों से जुड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।</p>	 <p style="text-align: center;"><a href="#">X link</a></p>

9)	<p>31 अप्रैल, 2025</p> <p>बेंगलुरु (कर्नाटक)</p>	<p><b>वक्फ विधेयक विरोध प्रदर्शन में कन्नड़ भाषा की अनुपस्थिति पर विवाद</b></p> <p>कर्नाटक के बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 31 अप्रैल 2025 को मुस्लिम लोगो द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमे प्रदर्शन स्थल पर जो बैनर, पोस्टर या बोर्ड लगाए गए थे, वे मुख्यतः उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी में थे, लेकिन स्थानीय भाषा कन्नड़ में कोई जानकारी नहीं दी गई।</p> <p>इस कारण स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों में नाराज़गी देखी गई, क्योंकि यह कर्नाटक की सांस्कृतिक अस्मिता का अपमान बताया।</p>	 <p><a href="#">X link</a></p>
----	--	---	---